



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127540

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 20657/2026

विवेक कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता:

राजेश कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत याचिका उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2(ख)(i)/3 के तहत मुकदमा संख्या 04/2026 में आवेदक की जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दायर की गई है। मामला कोतवाली नगर पुलिस थाना, जिला बांदा का है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक की ओर से यह भी कहा गया है कि उसके खिलाफ गैंग चार्ट में पांच मामले दर्ज हैं और इन सभी मामलों में वह जमानत पर है। गैंग चार्ट में दर्ज इन पांच मामलों के अलावा, आवेदक का चार और आपराधिक अभिलेख है, जिसका जमानत याचिका के समर्थन में दायर हलफनामे के परिच्छेद संख्या 8 में विधिवत विवरण दिया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि सह-आरोपी अरविंद कुशवाहा और संतलाल उर्फ निराला को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा दिनांक 12.03.2026 और 22.04.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6135/2026 और 13179/2026 में पारित आदेशों के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

4. उन्होंने आगे कहा कि विचाराधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट में, आवेदक के विरुद्ध सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने और अनुचित लौकिक, आर्थिक, भौतिक या इसी प्रकार का अन्य लाभ प्राप्त करने के आरोप अस्पष्ट हैं। उन्होंने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत "गिरोह" और "गिरोहबंद" की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले किसी आरोपी द्वारा किए गए कृत्य या चूक से संबंधित आरोप के अभाव में, कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट विचारणीय नहीं है। इस मामले में, प्रथम सूचना रिपोर्ट लंबित आपराधिक मामलों पर आधारित है, न कि किसी नए आरोप या ऐसे तथ्यों की खोज पर, जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता हो, जिसके लिए यह अधिनियम बनाया गया था।

5. उन्होंने यह भी कहा कि अधिनियम के प्रावधानों का इस्तेमाल प्रतिशोध लेने, नागरिकों को परेशान करने या डराने-धमकाने या राजनीतिक या अन्य मोर्चों पर हिसाब बराबर करने के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता।

6. उन्होंने कहा कि इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन ने अच्छा काम दिखाने, वाहवाही बटोरने या सरकार या सत्ताधारी दल के उच्च अधिकारियों से प्रशंसा पाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों का अनुचित रूप से इस्तेमाल किया है।

7. उन्होंने यह भी कहा कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह मानने के पर्याप्त आधार हैं कि आवेदक गिरोहबंद अधिनियम के तहत अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए वह अपराध नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जमानत पर रहते हुए आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा और न ही वह किसी भी तरह से सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करेगा।

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक इस मामले में 25.08.2025 से जेल में बंद है और ऐसी कोई आशंका नहीं है कि यदि आवेदक को जमानत दी जाती है, तो वह कानून से भाग जाएगा या विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं होगा। साथ ही, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य/सामग्री इतनी मजबूत नहीं है कि यह अनुमान लगाया जा सके कि आवेदक गिरोह चार्ट में उल्लिखित अपराधों का दोषी है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

10. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया है कि गिरावट चार्ट में उल्लिखित मामलों में आवेदक जमानत पर है। उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि उपरोक्त सह-आरोपियों को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि आवेदक एक गिरावट का सदस्य है और अपराध करने का आदी है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होगा और अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाकर और डराकर जमानत का दुरुपयोग करेगा।

11. उत्तर प्रदेश गिरावट और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) इस प्रकार है:-

"(4) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को, यदि वह हिरासत में है, तो जमानत पर या अपने मुचलके पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि--
(क) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय संतुष्ट हो कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।"

12. उत्तर प्रदेश गिरावट और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) के आलोक में, मैंने अभिलेख पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य, गैंग-चार्ट में उल्लिखित अपराध की प्रकृति और आरोपी-आवेदक की आपराधिक पृष्ठभूमि पर विचार किया है।

13. यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एस.सी.सी. 713 मामले में कई निर्णयों में यह माना गया कि संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के संरक्षण में न केवल उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता बल्कि न्याय तक पहुंच और शीघ्र सुनवाई भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



लीगल एड कमेटी रिप्रेजेंटिंग अंडरट्रायल प्रिजनर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में यह माना गया कि विचाराधीन कैदियों को मुकदमे की सुनवाई तक अनिश्चित काल के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता। आदर्श रूप से, किसी भी व्यक्ति को अपने कृत्यों के प्रतिकूल परिणामों का सामना नहीं करना चाहिए जब तक कि यह किसी निष्पक्ष मध्यस्थ के समक्ष सिद्ध न हो जाए। हालांकि, वास्तविक जीवन की व्यावहारिकतागण के कारण, जहां प्रभावी सुनवाई सुनिश्चित करने और मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने के दौरान संभावित अपराधी को रिहा किए जाने की स्थिति में समाज के लिए जोखिम को कम करने के लिए, न्यायालयों को यह तय करना होता है कि किसी व्यक्ति को मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने के दौरान रिहा किया जाना चाहिए या नहीं। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि समय पर सुनवाई संभव नहीं होगी और आरोपी काफी समय तक कारावास में रह चुका है, तो न्यायालय आमतौर पर उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए बाध्य होते हैं।

14. उपर्युक्त पक्षों की दलीलों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2018) 3 एससीसी 22 तथा सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई और अन्य (एसएलपी (आपराधिक) संख्या 5191/2021)** के मामलों में दिए गए निर्णयों पर विचार करने के बाद, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

15. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **विवेक कुमार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक यह वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दंड संहिता/ 269 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता/ 84 भारतीय न्याय संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए भारतीय दंड संहिता/ 209 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता/ 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

16. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से माननीय विचारण न्यायालय को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

16 जून, 2026

राधिका

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"